

नरेगा संघर्ष मोर्चा (एनएसएम) और पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीईजी) द्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च, 2022

नरेगा पर मोदी सरकार का हमला जारी: वित्त वर्ष 2022-23 में नरेगा के लिए बेहद कम मजदूरी दरें

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नरेगा श्रमिकों के लिए दिनांक 28 मार्च 2022 को मजदूरी दर अधिसूचित की गई थी। अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत के 3 दिन पहले वेतन दर अधिसूचित करना काफी देरी को दर्शाता है। इस तरह की देरी मजदूरी दरों या उनकी पर्याप्तता के बारे में किसी प्रकार चर्चा या बहस को रोकती है। यह नरेगा पर सरकार के हमले का सिलसिला है और इसने एक बार फिर केंद्र सरकार की नरेगा श्रमिकों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को उजागर किया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बढ़ोतरी मात्र 4 रुपये से लेकर अधिकतम 21 रुपये तक है और 3 राज्यों (मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा) के श्रमिकों को बिना किसी बढ़ोतरी के संतोष करना होगा। देश भर में नरेगा मजदूरी दर में औसत वृद्धि मात्र 4.25% हुई है। जबकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31% का महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जिसकी कीमत हर साल सरकारी खजाने में 9,544.50 करोड़ रुपए होती है। जहां सरकार साल में दो बार डीए को संशोधित करती है और इसके लिए हजारों करोड़ का भुगतान करती है, वहीं नरेगा श्रमिकों की व्यवस्थित रूप से उपेक्षा की जाती है।

एक आधारभूत मजदूरी होने के कारण नरेगा मजदूरी में वृद्धि द्वारा ग्रामीण और आने वाले समय में शहरी औद्योगिक मजदूरी की बढ़ोतरी के मांग का दबाव बढ़ेगा। वर्तमान आर्थिक संकट के समय में, यह ग्रामीण व्यय में भी वृद्धि करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के कुल मांग में वृद्धि होगी, जो इसकी बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है।

Table 1:

Select States	NREGA Wage Rate FY 2021-22	NREGA Wage Rate FY 2022-23	Increase in Wage Rate	% Increase in Wage Rate
A	B	C	D = C - B	E = (D/B)*100
Karnataka	289	309	20	6.92
Kerala	291	311	20	6.87
Jammu & Kashmir	214	227	13	6.07
Bihar	198	210	12	6.06
Jharkhand	198	210	12	6.06
Chhattisgarh	193	204	11	5.70
Madhya Pradesh	193	204	11	5.70

Haryana	315	331	16	5.08
Andhra Pradesh	245	257	12	4.90
Telangana	245	257	12	4.90
Punjab	269	282	13	4.83
Himachal Pradesh: Non-Scheduled Areas	254	266	12	4.72
West Bengal	213	223	10	4.69
Rajasthan	221	231	10	4.52
Himachal Pradesh: Scheduled Areas	203	212	9	4.43
Uttar Pradesh	204	213	9	4.41
Uttarakhand	204	213	9	4.41
Gujarat	229	239	10	4.37
Odisha	215	222	7	3.26
Maharashtra	248	256	8	3.23
Tamil Nadu	273	281	8	2.93
Assam	224	229	5	2.23
All India Average	239.30	249.46	10.16	4.25

Source: MGNREGA wage rate data is from Ministry of Rural Development notification

27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नरेगा मजदूरी दर कृषि न्यूनतम मजदूरी से कम है जो श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी के एक और वर्ष झेलने पर मजबूर करता है। कर्नाटक में सबसे अधिक अंतर है (मजदूरी दर में उच्चतम% वृद्धि होने के बावजूद) जहां नरेगा मजदूरी दर राज्य के कृषि न्यूनतम मजदूरी का केवल 70 प्रतिशत है। झारखंड, ओडिशा, बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों के लिए यह अनुपात लगभग 70 प्रतिशत है। देश के लिए नरेगा मजदूरी दरों और न्यूनतम मजदूरी दर के बीच कुल औसत अंतर लगभग 20 प्रतिशत है।

Table 2:

Select States	NREGA Wage Rate in FY 2022-23	Agricultural Minimum Wage Rate	Difference Between FY 2022-23 Wage Rate and Agricultural Minimum Wage Rate	NREGA Wage Rate as proportion of the Agricultural Minimum Wage Rate
A	C	F	G = C - F	H = (C/F)*100
Jharkhand	210	315	-105	66.67
Karnataka	309	441	-132	70.07
Odisha	222	315	-93	70.48

Himachal Pradesh: Scheduled Areas	212	300	-88	70.67
Bihar	210	292	-82	71.92
Kerala	311	410	-99	75.85
Punjab	282	369	-87	76.42
Assam	229	298	-69	76.85
Gujarat	239	310	-71	77.10
Chhattisgarh	204	262	-58	77.86
West Bengal	223	268	-45	83.21
Telangana	257	306	-49	83.99
Uttarakhand	213	245	-32	86.94
Tamil Nadu	281	322	-41	87.27
Haryana	331	377	-46	87.80
Andhra Pradesh	257	292	-35	88.01
Himachal Pradesh: Non-Scheduled Areas	266	300	-34	88.67
Madhya Pradesh	204	228	-24	89.47
Rajasthan	231	252	-21	91.67
Maharashtra	256	276	-20	92.75
Uttar Pradesh	213	201	12	105.97
Jammu & Kashmir	227	225	2	100.89
All India Average	244.86	302.08	-57.22	81.06

Source: V V Giri National Labour Institute & state notifications for minimum wages, Retrieved from <https://timesofindia.indiatimes.com/india/mnregs-workers-subsidised-creation-of-infra-assets-by-rs-20000-crore-a-year/articleshow/89125423.cms> and <https://paycheck.in/salary/minimumwages>

ऐसे समय में जब देश दशकों में सबसे खराब रोजगार संकट से गुज़र रहा है, तब नरेगा मजदूरी में यह मामूली बढ़ोतरी गरीबों पर एक बहुप्रचारित "सर्जिकल स्ट्राइक" से कम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, बेरोजगारी दर ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू गई है और लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। गरीब अभी भी महामारी के कारण ग्रामीण संकट से उबर रहे हैं जिसके कारण देश भर में लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे परिदृश्य में, मनरेगा ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक जीवन रेखा रही है जो जरूरत और संकट के समय में काम और नकदी प्रदान करती है। यह विडंबना ही है कि जब देश आर्थिक सुधार के पथ पर चल रहा है, उसी अवधि में ग्रामीण मजदूरी स्थिर रही है और धन की गंभीर कटौती के कारण राज्य व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम को संचालित करने में कमजोर कर रहा है।

नरेगा मजदूरी को राज्य की न्यूनतम मजदूरी (महेंद्र देव समिति द्वारा) के साथ जोड़ने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के सुझाव, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - ग्रामीण मजदूर (CPI-R) के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - कृषि मजदूर (CPI-AL) के लिए मजदूरी दर को अनुक्रमित करना (नागेश सिंह समिति द्वारा), या अनूप सत्पथी समिति द्वारा अनुशंसित प्रति दिन रु.375 के बावजूद सरकार ने इन सुझाव को लागू नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने भी यह सुझाव दिया था कि नरेगा मजदूरी दर को CPI-R में अनुक्रमित किया जाए। इन सुझाव के बावजूद, नरेगा मजदूरी दरों में मामूली वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति में होने वाली वृद्धि और जीवन यापन की लागत के अनुपात में नहीं रही है।


सरकार हर साल नरेगा मजदूरी दर की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली को सार्वजनिक नहीं करती है। यह न केवल मजदूरी दरों पर चर्चा को रोकता है, बल्कि अधिनियम की पारदर्शी और जवाबदेही की भावना के खिलाफ भी है। झारखंड जैसे कई राज्यों (198 रुपये से 225 रुपये) ने केंद्र द्वारा निर्धारित मौजूदा राशि से मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के राज्य बजट से जोड़ा है। कुल मिलाकर राज्य सरकारें गरीबों के पक्ष में श्रम बाजार और मजदूरी दरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ाने के बजाय लोकलुभावन कार्यों और दान पर खर्च करेंगी। यह किसी मजाक से कम नहीं है कि सरकारें श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार न्यूनतम मजदूरी को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा है और इससे कम किसी प्रकार के भुगतान को "बंधुआ मजदूरी" के अनुरूप माना है। हास्यास्पद रूप से कम बजट आवंटन, गैर-लाभकारी नरेगा मजदूरी, मजदूरी भुगतान में लंबी देरी के साथ-साथ कई मामलों में मजदूरी का भुगतान न करने के कारण ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम से दूर कर दिया है। कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण नागरिकों को रोजगार गारंटी की सच्ची भावना एवं मांग-संचालित कार्यक्रम के रूप में स्थापित करना होगा जिसकी परिकल्पना कानून के स्थापना के साथ की गई थी।

नरेगा संघर्ष मोर्चा और पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी इस मजदूर विरोधी फैसले की कड़ी निंदा करता है तथा नरेगा मजदूरी दर में 600 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि के साथ-साथ समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाए। यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का पालन करता है जिसके अनुसार छह साल पहले अक्टूबर 2016 में न्यूनतम मासिक वेतन के रूप में 18,000 निर्धारित की गई थी, जिसके बाद कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया nrega.sangharsh.morcha@gmail.com ; paeg.india@gmail.com पर लिखें या संपर्क करें:

निखिल डे (9910421260) | देबमाल्या (7294184845) | राजेंद्रन नारायणन (9620318492) | चक्रधर (9246522344) | विजय राम एस (9597928778) | अपूर्वा (9313759050) | अनुज गोयल (8368042125)

Table 3:  Annexure For a more detailed analysis of the wage rate data, please refer to the linked annexure.

State	NREGA Wage Rate FY 2021-22	FY 2022-23 NREGA Wage Rate	% Increase in NREGA Wage Rate	Average Rural Inflation Rate (June 2021-Feb 2022)	Inflation Adjusted 2021-22 Wage Rate	Difference Between Inflation Adjusted 2021-22 Wage Rate and FY 2022-23 Wage Rate ¹	Difference Between % Increase in NREGA Wages and Rural Inflation Rate ²
A	B	C	$E = \frac{C-B}{B} \times 100$	I	$J = \frac{B \times (100+I)}{100}$	$K = C - J$	$L = E - I$
Andhra Pradesh	245	257	4.90	5.30	257.97	-0.97	-0.40
Assam	224	229	2.23	3.54	231.93	-2.93	-1.31
Bihar	198	210	6.06	4.07	206.05	3.95	1.99
Chhattisgarh	193	204	5.70	4.11	200.93	3.07	1.59
Gujarat	229	239	4.37	5.85	242.40	-3.40	-1.48
Haryana	315	331	5.08	6.42	335.24	-4.24	-1.34
Jammu & Kashmir	214	227	6.07	7.42	229.87	-2.87	-1.35
Jharkhand	198	210	6.06	3.10	204.14	5.86	2.96
Karnataka	289	309	6.92	5.32	304.36	4.64	1.60
Kerala	291	311	6.87	3.68	301.71	9.29	3.19
Madhya Pradesh	193	204	5.70	6.44	205.44	-1.44	-0.74
Maharashtra	248	256	3.23	6.40	263.86	-7.86	-3.17
Odisha	215	222	3.26	2.92	221.28	0.72	0.34
Punjab	269	282	4.83	5.03	282.54	-0.54	-0.20
Rajasthan	221	231	4.52	4.67	231.32	-0.32	-0.15
Tamil Nadu	273	281	2.93	5.46	287.90	-6.90	-2.53
Telangana	245	257	4.90	7.82	264.15	-7.15	-2.92
Uttar Pradesh	204	213	4.41	5.77	215.77	-2.77	-1.36
Uttarakhand	204	213	4.41	4.27	212.72	0.28	0.14
West Bengal	213	223	4.69	5.56	224.85	-1.85	-0.87
All India Average	239.30	244.86	2.33	5.33	252.05	-7.19	-3.00

¹ In column K, a negative number means that the inflation adjusted FY 2021-22 wage rate is higher than the wage rate for FY 2022-23. In other words, the NREGA wage rate for this year is less than the wage rate of last year, in terms of the real incomes earned by workers.

² Similarly, in column L, a negative number indicates that the NREGA wage rate for FY 2022-23 has not increased even as much as the rural inflation rate till February 2022.